गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 352
दि. 25.04.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

सियासत में बड़ा पलटवार: आप के सात सांसदों का भाजपा में विलय, राजनीतिक भूचाल

नई दिल्ली की सियासी फिजा में शुक्रवार का दिन एक बड़े घटनाक्रम का गवाह बना, जब आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे राघव चड्ढा ने पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यह केवल एक नेता का दल परिवर्तन नहीं था, बल्कि राज्यसभा में आप की ताकत को झकझोर देने वाला ऐसा कदम था, जिसने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। राघव के साथ ही संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रजीत सिंह साहनी, राजिंदर गुप्ता और स्वाती मालीवाल जैसे नाम भी इस राजनीतिक बदलाव का हिस्सा बन गए, जिससे आम आदमी पार्टी को एक साथ सात सांसदों का बड़ा झटका लगा। राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम की गूंज इसलिए भी ज्यादा सुनाई दी क्योंकि यह वही राघव चड्ढा हैं, जिन्हें हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में उप नेता पद से हटा दिया था। पार्टी ने उन पर सरकार के खिलाफ मुखर न होने और 'सॉफ्ट पीआर' करने जैसे आरोप लगाए थे। लेकिन घटनाओं ने अचानक ऐसा मोड़ लिया कि जिन अशोक मित्तल को उनकी जगह जिम्मेदारी दी गई थी, वे भी राघव के साथ भाजपा में शामिल होते नजर आए। खास बात यह भी रही कि मित्तल के खिलाफ हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई थी, और उसके महज दस दिन बाद उनका यह राजनीतिक निर्णय सामने आया।

दल बदल की इस बड़ी पटकथा का अगला दृश्य भाजपा मुख्यालय में देखने को मिला, जहां राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने पहुंचकर भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। स्वागत के तौर पर गुलदस्ते भेंट किए गए, मिठाई खिलाई गई और औपचारिक फोटो सेशन के साथ इस नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की गई। यह पूरा दृश्य केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक गठजोड़ का संकेत था, जो आने वाले समय में कई समीकरण बदल सकता है।

इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी खुद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि संविधान के प्रावधानों के तहत आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के दो-तिहाई से अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी

में विलय कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि कुल सात सांसदों ने इस विलय संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं और इन्हें राज्यसभा के सभापति को सौंपा गया है। राघव ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला उन्होंने पूरी सोच-विचार के बाद लिया है और उनका मानना है कि पार्टी अब अपने मूल सिद्धांतों और मूल्यों से भटक चुकी है।

राघव चड्ढा ने अपने संबोधन में भावनात्मक अंदाज में कहा कि उन्होंने अपने जीवन के 15 साल आम आदमी पार्टी को दिए, उसे खून-पसीने से सींचा, लेकिन अब उन्हें यह महसूस हो रहा है कि पार्टी की दिशा बदल चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अब राष्ट्रीय हितों की बजाय व्यक्तिगत लाभ की राजनीति में उलझ गई है। उनका यह बयान न केवल उनके निर्णय को जायज ठहराने की कोशिश थी, बल्कि यह आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर भी सीधा सवाल था। इस घटनाक्रम ने जहां भाजपा को एक बड़ा राजनीतिक लाभ दिया, वहीं आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हुआ।

पार्टी की ओर से सबसे पहले प्रतिक्रिया संजय सिंह ने दी। उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह 'ऑपरेशन लॉट्स' का हिस्सा है, जिसके जरिए पंजाब की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में अच्छा काम किया है और इसी से घबराकर भाजपा इस तरह के हथकंडे अपना रही है।

वहीं पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा ने एक बार फिर पंजाबियों के साथ धोखा किया है। उनका यह बयान इस बात का संकेत था कि पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को केवल दल-बदल नहीं, बल्कि एक राजनीतिक साजिश के रूप में देख रही है।

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू दल-बदल विरोधी कानून का है। वर्तमान में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सदस्य हैं, जिनमें से सात सांसदों का एक साथ पार्टी छोड़ना और भाजपा में शामिल होना इस कानून के तहत महत्वपूर्ण हो जाता है। नियमों के अनुसार, किसी भी दल के संसदीय दल के विलय के लिए कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। यानी 10 में से कम से कम 7 सांसदों का एक साथ जाना इस विलय को कानूनी रूप से वैध बना सकता है और इससे उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं रहेगा।

राघव चड्ढा ने दावा किया है कि उनके साथ राज्यसभा में आप के दो-तिहाई सदस्य हैं, जिससे यह विलय पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किया गया है। हालांकि, इस दावे की अंतिम पुष्टि राज्यसभा के सभापति द्वारा ही की जाएगी, जिनके पास अब यह मामला विचाराधीन है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह घटनाक्रम केवल एक दल बदल की कहानी नहीं है, बल्कि यह आने वाले चुनावों के लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। खासकर पंजाब की राजनीति में इसका असर देखने को मिल सकता है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया है कि भारतीय राजनीति में कब क्या हो जाए, इसका अनुमान लगाना बेहद कठिन है। कल तक जो नेता एक पार्टी के लिए समर्पित नजर आते हैं, वे आज दूसरी पार्टी का झंडा थाम लेते हैं। यह बदलाव केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं होते, बल्कि इनके पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक कारण छिपे होते हैं।

नई दिल्ली से शुरू हुई यह राजनीतिक कहानी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बड़े राजनीतिक बदलाव का असर न केवल आम आदमी पार्टी और भाजपा पर, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर किस तरह पड़ता है। फिलहाल इतना जरूर है कि इस घटनाक्रम ने सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है, जिसका असर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा।

संकट के बाद राहत: व्यावसायिक एलपीजी और यूरिया आपूर्ति पटरी पर, बाजार में स्थिरता के संकेत

नई दिल्ली। ऊर्जा आपूर्ति को लेकर हालिया दबाव के बीच केंद्र सरकार की सक्रिय रणनीति के सकारात्मक परिणाम अब जमीन पर दिखने लगे हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने जानकारी दी कि देश में व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति लगभग 70 प्रतिशत तक बहाल हो चुकी है। यह आंकड़ा न केवल राहत देने वाला है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि आपूर्ति श्रृंखला धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रही है।

उन्होंने बताया कि अप्रैल माह में अब तक 1.47 लाख टन से अधिक व्यावसायिक एलपीजी की बिक्री हो चुकी है, जो बाजार में मांग और उपलब्धता के बीच संतुलन बनने का संकेत है। खास तौर पर छोटे व्यापारियों और रेस्तरां संचालकों के लिए यह राहत की खबर है, जो एलपीजी आपूर्ति में आई बाधाओं के कारण प्रभावित हुए थे। पांच किलो वाले छोटे सिलिंडरों की बिक्री भी सुचारू रूप से जारी है, और हाल ही में एक ही दिन में 81,000 से अधिक सिलिंडर बिकना इस बात का प्रमाण है कि वितरण व्यवस्था अब बेहतर

तरीके से काम कर रही है।

ऊर्जा क्षेत्र के साथ-साथ कृषि से जुड़े मोर्चे पर भी सरकार ने महत्वपूर्ण प्रगति का दावा किया है। सुजाता शर्मा के अनुसार, यूरिया उर्वरक संयंत्रों के लिए आवश्यक आपूर्ति लगभग 95 प्रतिशत तक बहाल कर दी गई है। यह विशेष रूप से किसानों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि यूरिया की उपलब्धता सीधे तौर पर फसल उत्पादन से जुड़ी होती है। आपूर्ति में आई यह बहाली आने वाले कृषि सीजन के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।

सरकार द्वारा अपनाई गई संकट निवारण योजना के तहत कई अहम कदम उठाए गए। इनमें घरेलू रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन बढ़ाना, कच्चे तेल और एलपीजी के कार्गो को समय रहते सुरक्षित करना, और घरेलू बाजार में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्यात शुल्क लगाना शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य स्पष्ट था—देश के भीतर मांग और आपूर्ति के संतुलन को बनाए रखना और किसी भी प्रकार की कमी को रोकना।

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय था। ऐसे में सरकार द्वारा समय रहते उठाए गए कदमों ने संभावित संकट को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया। इससे न केवल औद्योगिक गतिविधियों को सहारा मिला, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिली है।

हालांकि, स्थिति पूरी तरह सामान्य होने में अभी कुछ समय लग सकता है, लेकिन मौजूदा आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि सुधार की दिशा सही है। बाजार में घबराहट की स्थिति कम हुई है और आपूर्ति व्यवस्था धीरे-धीरे स्थिर हो रही है। आने वाले दिनों में यदि यही रफ्तार बनी रहती है, तो एलपीजी और उर्वरक दोनों क्षेत्रों में पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है।

सरकार का यह भी कहना है कि भविष्य में इस तरह के संकटों से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों पर भी काम किया जा रहा है, ताकि देश की ऊर्जा और कृषि जरूरतों को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके। फिलहाल, आपूर्ति में आई यह बहाली आम जनता और उद्योग जगत दोनों के लिए राहत की खबर बनकर सामने आई है।

झालमुड़ी बनाम भेलपुरी: बंगाल चुनाव में स्वाद के जरिए सियासी तकरार तेज

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की चुनावी सरगर्मी के बीच राजनीतिक बयानबाज़ी अब दिलचस्प मोड़ लेती दिख रही है, जहां विकास, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दों के साथ-साथ अब खाने-पीने की चीजें भी चुनावी संवाद का हिस्सा बन गई हैं। बौबाजार में आयोजित एक रैली में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए 'झालमुड़ी' और 'भेलपुरी' के उदाहरण से अपनी बात रखी, जिसने पूरे चुनावी माहौल में एक नई बहस को जन्म दे दिया।

अपने चिर-परिचित अंदाज में ममता बनर्जी ने कहा कि "वे झालमुड़ी का वादा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको भेलपुरी खिलाऊंगी।" यह बयान महज एक तंज नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झारग्राम में प्रधानमंत्री के झालमुड़ी खाने का कार्यक्रम पूर्व-नियोजित था और इसे आम लोगों के बीच जुड़ाव दिखाने के लिए एक 'सजाया गया दृश्य' बनाया गया।

मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में कई सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि जिस दुकान पर प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई, वहां पहले से ही सीसीटीवी और टीवी कैमरे लगाए गए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि पूरा कार्यक्रम

पहले से तैयार किया गया था। ममता बनर्जी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि "सुरक्षा के नाम पर झालमुड़ी घर से बनाकर लाई गई थी और दुकानदार को केवल 10 रुपये दिए गए।" उनके इस बयान ने रैली में मौजूद समर्थकों के बीच हंसी और तालियों का माहौल बना दिया, लेकिन साथ ही यह राजनीतिक कटाक्ष भी साफ तौर पर सामने आया।

भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए इस तरह के प्रतीकात्मक और भावनात्मक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता को आकर्षित करने के लिए 'झालमुड़ी' जैसे स्थानीय प्रतीकों का इस्तेमाल कर रही है, जबकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। इसके जवाब में उन्होंने 'भेलपुरी' का उदाहरण देते हुए कहा कि वे लोगों को बेहतर विकल्प देने की बात कर रही हैं।

ममता बनर्जी का यह बयान केवल खाने की तुलना तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने इसे सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समावेश के बड़े संदर्भ में भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग तीखी झालमुड़ी के आदी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अन्य राज्यों के खान-पान से अनजान हैं। उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया जो देश की विविधता को अपनाता है।

उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वे ढोकला खाती हैं, डोसा खाती हैं, लिट्टी, ठेकुआ और सत्तू भी पसंद करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने ईद के अवसर पर सेवइयां और हलवा खाने का भी जिक्र किया। उनका यह बयान स्पष्ट रूप से यह संदेश देने के लिए था कि वे सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करती हैं और किसी एक पहचान तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने कहा, "मुझे धर्म मत सिखाइए," जो सीधे तौर पर उनके विरोधियों पर निशाना था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी का यह बयान एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वे खुद को एक समावेशी और जमीनी नेता के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झालमुड़ी खाने की घटना को लेकर उठाए गए सवाल भाजपा के जनसंपर्क अभियान पर सवाल खड़े करने की कोशिश माने जा रहे हैं। यह भी देखा जा रहा है कि चुनावी रैलियों में इस तरह के हल्के-फुल्के लेकिन तीखे बयान मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने में प्रभावी साबित होते हैं। खासकर बंगाल जैसे राज्य में, जहां राजनीतिक संवाद में सांस्कृतिक प्रतीकों की अहम भूमिका होती है, ऐसे बयान तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल राजनीतिक विचारधाराओं का मुकाबला नहीं, बल्कि प्रतीकों, भावनाओं और सांस्कृतिक पहचान का भी संघर्ष बन चुका है। जहां एक ओर भाजपा अपने तरीके से जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस भी उसी अंदाज में जवाब दे रही है।

आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह 'झालमुड़ी बनाम भेलपुरी' की बहस किस तरह आगे बढ़ती है और क्या यह वास्तव में मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर पाती है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि इस बयान ने चुनावी माहौल को और ज्यादा जीवंत और प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया है, जहां हर शब्द और हर प्रतीक का राजनीतिक अर्थ निकाला जा रहा है।

निर्वासन पर न्यायिक सख्ती: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब मानवीय और संवैधानिक सवालों के बीच बढ़ी संवेदनशीलता

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश भेजे गए लोगों की भारत वापसी से जुड़े बेहद संवेदनशील मामले में सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। अदालत ने केंद्र को आखिरी मौका देते हुए कहा है कि वह इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख सामने रखे, अन्यथा पीठ अंतिम सुनवाई की दिशा में आगे बढ़ेगी। इस टिप्पणी ने न केवल कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि मानवाधिकार और नागरिकता से जुड़े गंभीर सवालों को भी केंद्र में ला दिया है।

यह मामला उन लोगों से जुड़ा है, जिन्हें संदिग्ध विदेशी मानते हुए भारत से बांग्लादेश सीमा के पार भेज दिया गया था और अब उनके परिजन उन्हें वापस लाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ कर रही है। अदालत ने केंद्र सरकार के वकील को निर्देश दिया है कि वह सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्देश लेकर अदालत को अवगत कराएं। याचिकाकर्ता भोडू शेख की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और संजय हेगड़े ने जोरदार दलीलें पेश कीं। उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले में केंद्र सरकार का अपना पक्ष स्पष्ट न करना उचित नहीं है, खासकर तब जब मामला मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हो। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत केंद्र को अंतिम अवसर दे रही है और यदि इस बार भी जवाब नहीं दिया गया, तो मामला आगे बढ़ाया जाएगा।

इस पूरे विवाद का सबसे मार्मिक पहलू एक गर्भवती महिला सुनाली खातून और

उसके छोटे बच्चे से जुड़ा है। पिछले वर्ष 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर उन्हें भारत में प्रवेश की अनुमति दी थी। इससे पहले उन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया था। अदालत ने उस समय पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि बच्चे की देखभाल की जाए और बीरभूम जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को महिला को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।

केंद्र सरकार की ओर से उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया था कि महिला और बच्चे को केवल मानवीय आधार पर प्रवेश दिया गया है और उन्हें निगरानी में रखा जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि सरकार उन्हें बांग्लादेशी नागरिक मानती है और उनकी भारतीय नागरिकता के दावे का विरोध करेगी। यही बिंदु अब पूरे विवाद का केंद्र बन गया है, जहां एक ओर मानवीय दृष्टिकोण है, वहीं दूसरी ओर नागरिकता और कानूनी प्रक्रिया का प्रश्न।

भोडू शेख का आरोप है कि उनका परिवार पिछले 20 वर्षों से दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी कर रहा था। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने बिना पर्याप्त जांच के उन्हें बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में लिया और कुछ ही दिनों में सीमा पार भेज दिया। यह आरोप इस मामले को और गंभीर बना देता है, क्योंकि यह प्रक्रिया की पारदर्शिता और कानूनी वैधता पर सवाल खड़ा करता है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि महिला यह साबित कर देती है कि वह भोडू शेख की बेटी है, तो यह उसकी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। यह टिप्पणी इस मामले के कानूनी पहलुओं को एक नई दिशा देती है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि पारिवारिक संबंध भी नागरिकता निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इस मामले में यह भी सामने आया है कि कुछ अन्य लोग, जिनमें खातून के पति भी शामिल हैं, अभी भी बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत से अनुरोध किया गया है कि उन्हें भी वापस भारत लाने का निर्देश दिया जाए। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने यह भी सुझाव दिया कि महिला को दिल्ली में रखने की बजाय उसके पिता के पास पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भेजना अधिक उपयुक्त होगा।

यह पूरा मामला तब और जटिल हो गया जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2025 को एक अहम फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के निर्वासन आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने सुनाली खातून और अन्य लोगों को 'अवैध प्रवासी' घोषित कर बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई को गैरकानूनी बताया और छह निर्वासित व्यक्तियों को एक महीने के भीतर भारत वापस लाने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि इस मामले में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। अदालत के अनुसार, गृह मंत्रालय के नियमों के तहत निर्वासन से पहले राज्य सरकार द्वारा उचित जांच आवश्यक थी, लेकिन इस मामले में जल्दबाजी में कार्रवाई की गई। इस पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस तरह की कार्रवाई देश के न्यायिक वातावरण को प्रभावित करती है।

यह भी सामने आया कि निर्वासित किए गए लोगों को बाद में बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिससे उनकी स्थिति और भी गंभीर हो गई। यह तथ्य इस पूरे मामले को केवल कानूनी नहीं, बल्कि मानवीय संकट के रूप में भी प्रस्तुत करता है।

अब जब मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, तो देशभर की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। यह केवल कुछ व्यक्तियों की वापसी का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत में नागरिकता, मानवाधिकार और कानूनी प्रक्रिया के पालन से जुड़े बड़े सवालों को सामने लाता है। अदालत का अगला कदम न केवल इन पीड़ित परिवारों के भविष्य को तय करेगा, बल्कि यह भी निर्धारित करेगा कि ऐसे मामलों में भविष्य में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस संवेदनशील मुद्दे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब कानून और मानवीयता के बीच संतुलन की बात आती है, तो न्यायपालिका की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और अदालत इस पूरे मामले को किस दिशा में ले जाती है।

संपादकीय

जीवनशैली के रोग

निस्संदेह, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की वह रिपोर्ट राष्ट्रीय चिंता बढ़ाने वाली है कि देश की पचास फीसदी आबादी जीवनशैली से जुड़े रोगों से ग्रस्त-त्रस्त है। यह भी फिक्र बढ़ाने वाला है कि एक दशक पहले देश में खान-पान, जीवन व्यवहार व तनाव से उपजे रोगों का प्रतिशत जहां 31 था, वो अब पचास फीसदी तक जा पहुंचा है। वहीं एक अच्छी बात यह है कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार व नये शोध अनुसंधान के चलते संक्रामक रोगों का प्रतिशत घटा है। लेकिन हमारे खानपान व जीवन व्यवहार में तेजी से आ रहे बदलावों के चलते लोग मोटापे, मधुमेह, तनाव व उच्च रक्तचाप जैसे रोगों के शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते जानलेवा संकट भी बढ़ रहा है। हमें स्वीकार करना होगा कि आजादी के बाद देश में आम आदमी के जीवन स्तर में किसी न किसी तरह सकारात्मक बदलाव आया है, जिसके चलते जीवनशैली भी बदली है। लेकिन पौष्टिक व शरीर की जरूरतों के अनुकूल भोजन न करने, शारीरिक निष्क्रियता, स्क्रीन टाइम बढ़ने से नींद की कमी आदि अनेक ऐसे कारण हैं जो इन रोगों के वाहक बनते हैं। इसमें आनुवंशिक रोगों की भी भूमिका है। धीरे-धीरे शरीर को खोखला करने वाले ये रोग कालांतर जानलेवा बन जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन भी चिंता जता रहे हैं कि भारत में विभिन्न रोगों से मरने वाले ज्यादातर लोगों की मौत की वजह संक्रामक रोग के बजाय जीवनशैली से जुड़े रोग हैं। जो हमारी गभीर चिंता का विषय होना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चिकित्सा विज्ञान की आशातीत प्रगति के चलते आम भारतीय की जीवन प्रत्याशा में इजाफा हुआ है, लेकिन जीवनशैली से जुड़े रोगों का बढ़ना इस कामयाबी पर पानी फेरने जैसा है। यही वजह है कि देश में स्वास्थ्य बीमा कारोबार में तेजी आई है, यह तेजी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। लेकिन ये बीमा कंपनियां रोग से बचाव में मदद करने के बजाय व्यक्ति के रोगों के इलाज को प्राथमिकता देती हैं।

हालांकि, देश में जीवनशैली से जुड़े रोगों से बचाव के लिये जागरूकता जरूर आई है। जिसके लिये राजग सरकार को श्रेय देना होगा। प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग का दुनिया में व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ है। यह जागरूकता भारत में भी है। लेकिन बड़ी आबादी अब भी इससे दूर है। प्रधानमंत्री 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम व अन्य मंचों से मोटापे से बचाव और खानपान में मिलेट अपनाने पर अक्सर बल देते नजर आते हैं। लेकिन इस पर सकारात्मक प्रतिसाद अपेक्षित अनुपात में नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि लोगों को महंगा इलाज कराने को बाध्य होना पड़ता है। विडंबना है कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसे रोगों से राहत के लिये डॉक्टर जीवनभर दवा खाने को कहते हैं। तमाम लोग निजी अस्पतालों में हृदयरोग आदि के महंगे इलाज से गरीबी की दलदल में फंस जाते हैं। कोरोना संकट के सबक हमें याद रखने चाहिए, जब लोगों ने जेवर, जमीन व मकान तक गिरवी रखकर अपना उपचार कराया। लेकिन यदि लोग शारीरिक सक्रियता बढ़ाएं, योग, ध्यान और व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं तो इन रोगों से बच सकते हैं। विडंबना यह है कि हमने परंपरागत भारतीय खाद्य पदार्थों की अनदेखी करके पश्चिमी व चीनी खाद्य विकल्पों को चुनना शुरू कर दिया है। जो हमारी जलवायु व शारीरिक प्रकृति के अनुरूप नहीं हैं। जंक फूड में रासायनिक पदार्थ नुकसानदायक हैं वहीं तले-भुने खाने ने मोटापे को बढ़ाया है। फिर हम शारीरिक श्रम करने से बचते हैं और आरामतलबी का जीवन जीते हैं। जिसके फलस्वरूप बढ़ा मोटापा कई रोगों का वाहक बन जाता है। देर रात तक मोबाइल व इंटरनेट पर सोशल मीडिया में सक्रिय रहने से हमारी नींद में खलल पड़ा है। नींद पूरी न होने से तनाव व अवसाद बढ़ा है। हमारा देर से भोजन करना, देर से सोना और सुबह देर से उठना भी रोगों का कारक बना है। हमने जबसे खाने में पारंपरिक पौष्टिकता के बजाय स्वाद को प्राथमिकता देनी शुरू की है, तभी से शरीर में जरूरी विटामिनों की कमी बढ़ी है। प्रदूषित खान-पान की भी इस संकट में भूमिका है। वहीं सहज-सरल व्यवहार हमारे स्वस्थ होने की गारंटी है।

बेनामी संपत्ति ने बिगाड़ा नेपाली राजनीति का खेल

"पहले सुदन ने ऐलान किया था, 'मैं राजनीति नहीं करूंगा, मंत्री नहीं बनूंगा' वो 'आरएसपी' से टिकट लेकर गोरखा-एक से चुनाव लड़े, और मंत्री भी बने। जेन-जी के जो भी मंत्री एक-एक करके नप रहे हैं, वो बालेन्द्र शाह के विरुद्ध विभीषण की भूमिका नहीं निभाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता।"

नेपाल में गृहमंत्री पद त्याग चुके सुदन गुरुंग कुछ ऐसी बात बोल जाते थे, जो ज़ेरे बहस होकर दूर तलक जाती। गुरुंग ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, 'जब आप गरीब पैदा होते हैं, तो यह आपकी गलती नहीं होती; लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं, तो यह आपकी गलती होती है। सरकार में शामिल होने से पहले धन कमाना पाप नहीं है; सरकार में शामिल होने के बाद भ्रष्टाचार कर के धन कमाना पाप है।' सुदन गुरुंग का यह एक ऐसा फ़लसफ़ा था, जो जैसे भी पैसा कमाने वालों को कुतर्क करने, और स्वयं को संतुष्ट करने का हथियार बन गया। जेन-ज़ी की एक और स्टार व पेशे से इंजीनियर, रक्षा बम ने सुदन गुरुंग को सलाह दी, कि वे अपने बयान को सुधारें। उन्होंने कहा, 'जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में असमर्थ हैं, उन्हें दोषी ठहराना आपके पद की गरिमा को कम करता है। फिल्मों के डायलॉग फिल्मों के लिए लिखे जाते हैं; असल ज़िंदगी अपने-आप में एक संघर्ष है।'

सुदन गुरुंग का माज़ी जो लोग जानते हैं, उनका भी मानना है, कि जेन-ज़ी आंदोलन के इस सुपर स्टार ने भयानक ग़रीबी देखी थी। अब अरबों की संपत्ति हो गई, तो ग़रीबी का मज़ाक़ उड़ा रहा है। नेपाल के गोरखा जिले में जन्मा 39 साल का सुदन गुरुंग, राजनीति में आने से पहले, पार्टियों और क्लबों में डीजे का काम किया करता था। फिर काठमांडू में कुछ लोगों से जुड़कर उसने 'ओएमजी' 'नाइटक्लब' चलाना शुरू किया। इन अनुभवों ने उसे बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना, टीम मैनेज करना और कई तरह के लोगों से मिलना-जुलना सिखाया।

2015 के गोरखा भूकंप के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत बदल गई। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, सुदन ने वॉलंटियर्स जमा किये। सैकड़ों लोग खाना, रहने की जगह और मदद पहुंचाने के लिए उनके साथ जुड़ गए। यह ग्रुप बाद में 'हामी नेपाल' बना, जो युवाओं का संगठन है। 'हामी नेपाल' ने पहले आपदा राहत पर ध्यान दिया। धीरे-धीरे कम्युनिटी वर्क, यूथ ट्रेनिंग और सिविक प्रोजेक्ट्स में भी फैल गया। इसने बाढ़, भूस्खलन और कोविड-19 संकट के दौरान पीड़ितों की मदद की।

सुदन गुरुंग की लीडरशिप में पूरे देश में युवा वॉलंटियर्स का एक मज़बूत नेटवर्क बनाया। वर्ष 2025 के जेन-ज़ी आंदोलन में, जब ओली सरकार ने सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया, तो 'हामी नेपाल' युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का एपीसेंटर बन गया, जिससे पता चला कि आपदा राहत से बना एक ग्रुप कैसे शांतिपूर्ण सिविक मूवमेंट चला सकता है। लेकिन, बात सिर्फ़ पोलिटिकल एक्टिविज़म तक सीमित नहीं थी। इस संस्था के पास अथाह पैसे आना बहस का विषय बना।

सुदन गुरुंग का गृह मंत्री बनना और मंत्रिपरिषद में वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले के बाद तीसरे नंबर पर रखा जाना, पार्टी में कई लोगों नागवार गुज़रा। लोगों ने आपत्ति की, कि पहली बार मंत्री बने गुरुंग को इतना सीनियर पोजीशन नहीं देना चाहिए था। दो हफ़्ते से भी कम समय में उनकी रैंक बदल दी गई। पहले नंबर पर प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह, दूसरे नंबर पर वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले, तीसरे नंबर पर विदेश मंत्री शिशिर खनाल, चौथे नंबर पर ऊर्जा मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ और पांचवे नंबर पर गृह मंत्री सुदन गुरुंग को रखा गया। यह भी आगे चलकर किरकिरी का कारण बना।

सुदन गुरुंग गृह मंत्रालय के बहुत सारे आदेश इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिये दिये थे। पद संभालने की रात ही, उन्होंने कार्की कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और तत्कालीन होम मिनिस्टर रमेश लेखक की गिरफ्तारी के लिए दबाव डाला। इस गिरफ्तारी से हंगामा मच गया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, 'वादा तो वादा होता हैः कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यह किसी से बदला नहीं है, यह तो बस न्याय की शुरुआत है।' ओली और लेखक की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पूर्व ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

हालांकि, कोर्ट ने कानूनी आधार, और सबूतों की कमी का हवाला देते हुए गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया। इसके बचाव में सुदन गुरुंग ने इंस्टाग्राम पर जवाब दिया, 'मुझे लगा था कि मंत्री बड़े हैं, अब जब कोर्ट बड़ा लग रहा है, तो मैं कानून की पढ़ाई शुरू करूंगा।' न्यायपालिका पर देश का गृहमंत्री इस तरह की टिप्पणी करे, वह शिष्टाचार की लक्ष्मण रेखा को पार करने वाला था। गृह मंत्रालय का मुखिया सोशल मीडिया पर अरेस्ट वारंट पोस्ट कर '1, 2, 3' कहकर अरेस्ट की गिनती करना शुरू कर दे, यह किसी को भी अजीब लग सकता है।

सुदन गुरुंग ने ऐलान किया था, कि मंत्री बनने के बाद वे सरकारी गाड़ी नहीं चलाएंगे, मगर उन्होंने जो प्राइवेट गाड़ी चलाई, वह उस कंपनी की थी, जिसमें उन्होंने हवाला के पैसे लगाए थे। पहले सुदन ने ऐलान किया था, 'मैं राजनीति नहीं करूंगा, मंत्री नहीं बनूंगा' वो 'आरएसपी' से टिकट लेकर गोरखा-एक से चुनाव लड़े, और मंत्री भी बने। ज़ेन-जी के जो भी मंत्री एक-एक करके नप रहे हैं, वो बालेन्द्र शाह के विरुद्ध विभीषण की भूमिका नहीं निभाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। उधर, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सर्वोच्च लीडरशिप का हाल 'समरथ को नहीं दोष गुसाईं' जैसा है। इस पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने को वाशिंग मशीन में ड्राई क्लीन कर के कैसे 'परमहंस' बनाया जाये, इस वास्ते प्रतिनिधिसभा संचालन नियमावली मसौदा समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

लामिछाने को पिछली सरकार के स्पीकर देवराज घिमिरे ने सस्पेंड कर दिया था, जब उन पर कोऑपरेटिव फ्रॉड केस के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। ज़मानत पर रिहा होने के बाद, लामिछाने ने स्पीकर से संसदीय बैठकों में शामिल होने की इजाज़त मांगी थी। सत्तारूढ़ आरएसपी के सांसद गणेश पराजुली की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा एकमत से तैयार किए गए ड्राफ्ट रेगुलेशंस के रूल 259 को इस तरह से तोड़-मरोड़कर पेश किया गया, ताकि लामिछाने के मार्ग में कोई बाधा उपस्थित न हो। ड्राफ्ट पर मंज़ूरी बाक़ी है, लेकिन उस पर 'इफ-बट' शुरू हो चुका है। मुख्य विपक्षी पार्टी, नेपाली कांग्रेस के सांसद, और रेगुलेशन ड्राफ़्टिंग कमेटी के सदस्य निष्कल राय का कहना है, 'हमारी पार्टी को रूल 259, और इसके प्रावधानों पर गंभीर आपत्तियां हैं।' बाहर, बेशक विरोध हो, लेकिन संसद में ये दो-तिहाई मतों से पास कराने का खेल कर सकते हैं !

प्रेरणा

बहाव में ही बसी है असली स्वतंत्रता

प्राचीन चीन की धरती पर एक ऐसा समय था जब राजमहलों की भव्यता और सत्ता का आकर्षण हर विद्वान को अपनी ओर खींचता था। उस समय के एक राजा ने जब महान दार्शनिक लाओत्से के ज्ञान और उनकी गहरी समझ के बारे में सुना, तो वह उनसे अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने निश्चय किया कि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति उसके राज्य के प्रशासन में उच्च पद पर होना चाहिए, ताकि राज्य की व्यवस्था और भी बेहतर हो सके। राजा ने अपने विश्वसनीय दूतों को भेजा, यह आशा करते हुए कि लाओत्से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे और राजसत्ता का हिस्सा बनेंगे।

दूत कई दिनों की यात्रा के बाद उस स्थान पर पहुंचे, जहां लाओत्से रहते थे। लेकिन वहां न तो कोई भव्य आश्रम था, न कोई शिष्यों की भीड़, और न ही किसी प्रकार का वैभव। वे एक साधारण नदी के किनारे खड़े थे, जैसे कोई आम व्यक्ति, शांत और स्थिर। उनकी दृष्टि बहते हुए जल पर टिकी हुई थी, मानो वे उसमें कोई गहरा रहस्य पढ़ रहे हों। दूतों को यह दृश्य थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वे जिस महान व्यक्ति से मिलने आए थे, वह किसी राजा की तरह नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य की तरह प्रकृति में खोया हुआ था।

दूतों ने आगे बढ़कर राजा का संदेश सुनाया। उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा कि राजा उनकी विद्वता से प्रभावित हैं और उन्हें अपने राज्य में एक उच्च पद देना चाहते हैं। यह सुनकर लाओत्से ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। वे बस हल्के से मुस्कुराए और फिर धीरे से नदी की ओर इशारा करते हुए बोले, "क्या तुम इस जल को देख सकते हो?" दूतों ने आश्चर्य से नदी की ओर देखा और बोले, "हाँ, यह अपनी दिशा में बह रहा है।" लाओत्से ने कहा, "क्या तुमने कभी देखा है कि यह जल किसी से प्रतिस्पर्धा करता है? यह कभी किसी को पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं करता, फिर भी यह सबसे आगे बढ़ता जाता है।"

दूत चुपचाप सुनते रहे। लाओत्से ने आगे कहा, "यह जल किसी पहचान या पुरस्कार की इच्छा नहीं रखता, फिर भी यह सबको जीवन देता है। खेतों को सींचता है, प्यास बुझाता है, और प्रकृति को संतुलित रखता है। इसकी सबसे बड़ी शक्ति इसके सहज बहाव में है, न कि किसी संघर्ष में।" यह कहते हुए उन्होंने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और उसे धीरे से नदी में डाल दिया। पत्ता बिना किसी प्रतिरोध के जल के साथ बहने लगा।

लाओत्से ने उस दृश्य की ओर संकेत करते हुए कहा, "देखो, यह पत्ता कितना हल्का है। यह धारा के साथ चल रहा है, इसलिए यह कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर यह धारा के विरुद्ध जाने की कोशिश करे, तो यह कहीं भी नहीं जा पाएगा। यही जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति जीवन के प्रवाह को स्वीकार कर लेता है, वह सहजता से आगे बढ़ता है। लेकिन जो हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, वह स्वयं ही बंध जाता है।"

यह बात केवल एक साधारण उदाहरण नहीं थी, बल्कि जीवन का गहरा दर्शन था। हम अक्सर अपने जीवन में हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं—संबंधों को, परिस्थितियों को, और यहां तक कि भविष्य को भी। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो। लेकिन जब चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होतीं, तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और अपने भीतर तनाव पैदा कर लेते हैं।

लाओत्से का संदेश यह था कि जीवन को जबरदस्ती अपनी दिशा में मोड़ने की बजाय, उसके साथ बहना सीखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए या निष्क्रिय हो जाना चाहिए। बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी कोशिशों के साथ-साथ परिणामों को स्वीकार करने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव कर पाते हैं।

आज के आधुनिक जीवन में यह शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां प्रतिस्पर्धा हर जगह है—काम में, शिक्षा में, और सामाजिक जीवन में। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है। लेकिन इस दौड़ में हम अक्सर अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है, एक यात्रा है।

जब हम सहजता को अपनाते हैं, तो हमारे भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति विकसित होती है। यह शक्ति किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि भीतर की स्थिरता से आती है। जैसे नदी का जल बिना शोर किए निरंतर बहता रहता है, वैसे ही एक सहज व्यक्ति बिना दिखावे के अपने जीवन में आगे बढ़ता है। उसे किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है।

लाओत्से ने दूतों को अंत में यह समझाया कि वह राजसत्ता का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सत्ता, पद और सम्मान के पीछे भागता है, वह धीरे-धीरे अपने भीतर के स्वभाव से दूर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप जीवन जीता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है।

दूतों ने यह सब सुना और उनके मन में गहरी शांति का अनुभव हुआ। वे समझ गए कि लाओत्से का ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके जीवन में भी दिखाई देता है। वे राजा के पास लौटे और पूरी घटना सुनाई। राजा ने भी यह समझ लिया कि हर महान व्यक्ति को पद और शक्ति से नहीं बांधा जा सकता। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी पद या प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की सहजता को बनाए रखने में है। जब हम अपने स्वभाव के अनुसार जीते हैं और जीवन के प्रवाह को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर पाते हैं। जो छोड़ना जानता है, वही वास्तव में पा सकता है। और जो बहना सीख जाता है, वह बिना संघर्ष के सबसे दूर तक पहुंच जाता है।

क्या हम कृत्रिम मेधा के प्रयोग से उत्पन्न संकटों के लिए तैयार हैं?

मानव सभ्यता के इतिहास में तकनीकी क्रांतियों ने सदैव हमारे अस्तित्व की दिशा को बदला है, किंतु वर्तमान में कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो तीव्र विस्तार हम देख रहे हैं, वह पूर्ववर्ती सभी आविष्कारों से मौलिक रूप से भिन्न है। यह केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि एक समानांतर बुद्धिमत्ता है जो हमारे सोचने, निर्णय लेने और सामाजिक ताने-बाने को समझने के पारंपरिक तरीकों को चुनौती दे रही है। आज जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या हम इस तकनीक से उत्पन्न संकटों के लिए तैयार हैं, तो उत्तर केवल तकनीकी प्रगति में नहीं, बल्कि हमारी नैतिक, कानूनी और सामाजिक तैयारियों में छिपा है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जेनेरेटिव एआई के उदय ने सूचनाओं की सत्यता पर एक गहरा प्रश्नचिह्न लगा दिया है। डीपफेक तकनीक और परिष्कृत एल्गोरिदम के माध्यम से जिस प्रकार से भ्रामक सूचनाएं या मिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही हैं, उसने न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है, बल्कि व्यक्तिगत गरिमा को भी जोखिम में डाल दिया है। अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रिपोर्टों के अनुसार, पिछले 2 वर्षों में एआई-जनित भ्रामक सामग्रियों में 900 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह स्थिति दर्शाती है कि हमारी कानूनी प्रणालियां और डिजिटल साक्षरता के मानक इस गति का मुकाबला करने में फिलहाल अक्षम सिद्ध हो रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो कृत्रिम मेधा का प्रभाव रोजगार के बाजारों पर अत्यंत गहरा और बहुआयामी होने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भविष्य की नौकरियों से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार, एआई और ऑटोमेशन के कारण अगले दशक में करोड़ों नौकरियों के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। जहाँ एक ओर यह तकनीक उत्पादकता बढ़ाने और नए प्रकार के व्यवसायों को जन्म देने की क्षमता रखती है, वहीं दूसरी ओर यह निम्न और मध्यम कौशल वाले श्रमिकों के लिए एक बड़ा विस्थापन संकट भी पैदा कर रही है। क्या हमारी शिक्षा प्रणालियां और कौशल विकास कार्यक्रम इस गति से परिवर्तित हो रहे हैं कि वे भविष्य की कार्यशक्ति को इस नई व्यवस्था के अनुकूल बना सकें? यह प्रश्न अनुत्तरित है क्योंकि विकासशील देशों में डिजिटल विभाजन आज भी एक कठोर वास्तविकता है। जब तक हम एक समावेशी तकनीकी ढांचे का निर्माण नहीं करते, तब तक कृत्रिम मेधा केवल वैश्विक असमानता को बढ़ाने का एक माध्यम बनकर रह जाएगी। इसके अतिरिक्त, एआई मॉडल्स के भीतर मौजूद 'एल्गोरिथमिक बायस' या पक्षपात एक और बड़ा संकट है, जो ऐतिहासिक डेटा के आधार पर लिंग, जाति और राष्ट्रीयता के प्रति पूर्वाग्रहों को अनजाने में सुदृढ़ कर रहा है।

तकनीकी सुरक्षा और स्वायत्त हथियारों का मुद्दा कृत्रिम मेधा के सबसे भयावह संकटों में से एक है। 'लीथल ऑटोनॉमस वेपन्स सिस्टम्स' या स्वायत्त घातक हथियार प्रणालियों का विकास वैश्विक शांति के लिए एक नई चुनौती पेश कर रहा है। जब युद्ध के मैदान में जीवन और मृत्यु का निर्णय एक एल्गोरिदम द्वारा लिया जाने लगेगा, तो मानवीय उत्तरदायित्व और युद्ध के अंतरराष्ट्रीय कानूनों का क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र और कई वैश्विक मानवाधिकार संगठनों ने इस पर नियंत्रण की अपील की है, लेकिन महाशक्तियों के बीच एआई की प्रतिस्पर्धा ने एक नई डिजिटल शीत युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। यह तकनीकी रेस हमें एक ऐसे बिंदु पर ले जा सकती है जहाँ नियंत्रण की लगाम मानव के हाथ से निकलकर मशीनों के पास चली जाए। सुरक्षा का अर्थ केवल भौतिक हथियारों से नहीं है, बल्कि डेटा की गोपनीयता और एल्गोरिदम के माध्यम से किए जाने वाले 'बिहेवियरल मैनिपुलेशन' या व्यवहारिक हेरफेर से भी है। बड़ी तकनीकी कंपनियाँ जिस प्रकार डेटा का एकत्रीकरण कर रही हैं, वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता को एक संकीर्ण घेरे में बंद कर रहा है।

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी कृत्रिम मेधा की तैयारी पर प्रश्न उठना लाजिमी है। विशाल एआई मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा और जल संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। एक शोध के अनुसार, एक बड़े लैंग्वेज मॉडल को प्रशिक्षित करने में उतनी कार्बन फुटप्रिंट पैदा होती है, जितनी पांच कारें अपने पूरे जीवनकाल में उत्सर्जित करती हैं। जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझती दुनिया के लिए यह एक अतिरिक्त भार है। इसलिए, जब हम एआई के संकटों की बात करते हैं, तो हमें 'सस्टेनेबल एआई' या संवहनीय कृत्रिम मेधा की दिशा में भी ठोस कदम उठाने होंगे। क्या हमारे पास ऐसी नीतियां हैं जो इन कंपनियों को पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी बना सकें? वर्तमान में अधिकांश विनियमन केवल लाभ और तकनीकी श्रेष्ठता पर केंद्रित हैं, जबकि पारिस्थितिक संतुलन को हाशिए पर धकेल दिया गया है।

निष्कर्षतः कृत्रिम मेधा के संकटों के लिए हमारी तैयारी अभी भी प्रारंभिक और खंडित अवस्था में है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'यूरोपीय संघ एआई अधिनियम' जैसे प्रयास एक सकारात्मक दिशा दिखाते हैं, लेकिन यह वैश्विक स्तर पर एक समान मानकों के बिना अपर्याप्त हैं। हमें एक ऐसे वैश्विक गठबंधन की आवश्यकता है जो न केवल तकनीक के विकास की निगरानी करे, बल्कि मानवीय मूल्यों, नैतिकता और न्याय को इसके केंद्र में रखे। तैयारी का अर्थ केवल उन्नत फायरवॉल बनाना नहीं है, बल्कि एक जागरूक समाज का निर्माण करना है जो सत्य और मिथ्या के बीच अंतर कर सके। कृत्रिम मेधा एक शक्तिशाली लहर की तरह है, जिसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन यदि हम इसके लिए सही बांध और नहरें तैयार नहीं करते, तो यह हमारी सामाजिक व्यवस्था के तटबंधों को नष्ट कर सकती है। हमें तकनीकी प्रगति के साथ-साथ अपनी नैतिक चेतना को भी उन्नत करना होगा, क्योंकि अंततः तकनीक का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, न कि उसका विनाश। समय कम है और चुनौतियां अपार हैं, अतः भविष्य की तैयारी के लिए हमें आज ही अपनी प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित करना होगा।

अभियान

नारायण भक्ति का अमृत: विष्णु चालीसा से जीवन में दिव्य परिवर्तन का अनुभव

सनातन धर्म की विशाल परंपरा में जब भी पालन, संरक्षण और संतुलन की बात आती है, तो मन स्वतः ही भगवान विष्णु की ओर आकर्षित हो जाता है। वे केवल देवता नहीं, बल्कि इस सृष्टि के आधार हैं, वह शक्ति हैं जो हर जीव के जीवन को संतुलित रखती है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य अपने मार्ग से भटकने लगता है, तब वही विष्णु विभिन्न अवतारों में आकर धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे दयालु, करुणामय और पालनहार प्रभु की भक्ति यदि सच्चे मन से की जाए, तो जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है।

गुरुवार का दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। इस दिन की गई पूजा, व्रत और साधना का प्रभाव अन्य दिनों की तुलना में अधिक फलदायी माना गया है। जब भक्त इस दिन पूरे विश्वास और समर्पण के साथ भगवान का स्मरण करता है, तो उसकी हर प्रार्थना सीधे प्रभु तक पहुंचती है। यह केवल आस्था नहीं, बल्कि अनुभव का विषय है, जिसे हर वह व्यक्ति महसूस कर सकता है, जो श्रद्धा के साथ भक्ति करता है।

भक्ति के अनेक मार्ग हैं, लेकिन उनमें से एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली मार्ग है विष्णु चालीसा का नियमित पाठ। यह चालीसा केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। इसमें भगवान विष्णु के गुणों का वर्णन है, उनकी महिमा का गुणगान है और उनके प्रति भक्त के समर्पण की झलक है। जब कोई व्यक्ति इसे नियमित रूप से पढ़ता है, तो उसका मन धीरे-धीरे शुद्ध होने लगता है और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं।

मनुष्य का जीवन अनेक उतार-चढ़ाव से भरा होता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, तो कभी असफलता—ये सब जीवन के हिस्से हैं। लेकिन जब व्यक्ति इन परिस्थितियों में अपने भीतर स्थिरता बनाए रखता है, तभी वह सच्चे अर्थों में सफल होता है। विष्णु चालीसा का पाठ इस स्थिरता को बनाए रखने में अत्यंत सहायक होता है। यह मन को एकाग्र करता है, विचारों को शुद्ध करता है और व्यक्ति को एक नई ऊर्जा से भर देता है। जब भक्त प्रभु का नाम लेता है, तो वह केवल शब्द नहीं बोलता, बल्कि वह अपने हृदय की गहराइयों से उन्हें पुकारता है। यह पुकार जब सच्चे मन से निकलती है, तो वह सीधे भगवान तक पहुंचती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की इस पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। वे हर उस व्यक्ति की सहायता करते हैं, जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। धन, वैभव और सफलता की इच्छा हर व्यक्ति के मन में होती है। लेकिन केवल इच्छा करने से यह सब प्राप्त नहीं होता। इसके लिए परिश्रम के साथ-साथ ईश्वर की कृपा भी आवश्यक होती है। जब व्यक्ति नियमित रूप से विष्णु चालीसा का पाठ करता है, तो उसके जीवन में धीरे-धीरे समृद्धि आने लगती है। उसके कार्यों में सफलता मिलने लगती है और उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगती है। यह सब प्रभु की कृपा का ही परिणाम होता है।

भक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक शांति। आज के समय में मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वह अशांत है। उसके पास साधन हैं, लेकिन संतोष नहीं है। इसका कारण यह है कि उसने अपने जीवन से भक्ति को दूर कर दिया है। जब व्यक्ति भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यह शांति उसे हर परिस्थिति में संतुलित रहने की शक्ति देती है।

कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के जीवन का भार स्वयं उठा लेते हैं। जब भक्त पूरी श्रद्धा के साथ उनकी शरण में आता है, तो उसके जीवन की कठिनाइयाँ धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि भक्ति की वह शक्ति है, जो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। विष्णु चालीसा का नियमित पाठ इस शक्ति को जागृत करता है और व्यक्ति को हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त करता है।

भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन इसमें निरंतरता आवश्यक है। केवल एक दिन या कुछ दिनों तक पाठ करने से उसका पूर्ण प्रभाव नहीं मिलता। जब व्यक्ति रोजाना नियमपूर्वक चालीसा का पाठ करता है, तभी उसे उसका वास्तविक लाभ मिलता है। यह एक साधना है, जिसे धैर्य और विश्वास के साथ करना होता है।

समय के साथ जब व्यक्ति इस साधना में आगे बढ़ता है, तो उसे अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन महसूस होता है। उसका मन शांत होने लगता है, उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है और उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। वह छोटी-छोटी बातों से परेशान होना छोड़ देता है और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने लगता है।

भगवान विष्णु की भक्ति केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग भी है। जब व्यक्ति भक्ति करता है, तो वह अपने भीतर के दोषों को दूर करता है और अपने आत्मिक स्वरूप के करीब पहुंचता है। यही वह अवस्था है, जहां से सच्ची मुक्ति की शुरुआत होती है।

जब कोई व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत विष्णु चालीसा के पाठ से करता है, तो उसका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। उसके कार्यों में सफलता मिलती है, उसके संबंध बेहतर होते हैं और उसका मन प्रसन्न रहता है। धीरे-धीरे यह आदत उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है और वह हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करने लगता है।

भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। यह उसे यह समझने में मदद करती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति करना भी है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तो उसका जीवन स्वतः ही संतुलित और सफल हो जाता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि विष्णु चालीसा केवल एक पाठ नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम है, जो व्यक्ति को भगवान के करीब ले जाता है। यह उसे उसके जीवन की हर समस्या से बाहर निकालने की शक्ति देता है और उसे एक नई दिशा प्रदान करता है। जब व्यक्ति पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, तो उसके जीवन में वह परिवर्तन आता है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती।

इसलिए यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति, सफलता और समृद्धि की कामना करते हैं, तो आज से ही भगवान विष्णु की भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। नियमित रूप से विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए और पूरे समर्पण के साथ प्रभु का स्मरण कीजिए। धीरे-धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन की हर समस्या दूर हो रही है, आपके मार्ग की हर बाधा समाप्त हो रही है और आपका जीवन एक नई रोशनी से भरता जा रहा है। यही नारायण भक्ति का चमत्कार है, यही वह मार्ग है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

सूरत नगर निगम चुनाव 2026: प्रचार थमा, लेकिन अंदरखाने तेज़ हुई सियासी हलचल; आखिरी दौर की रणनीति पर टिकी सभी की निगाहें

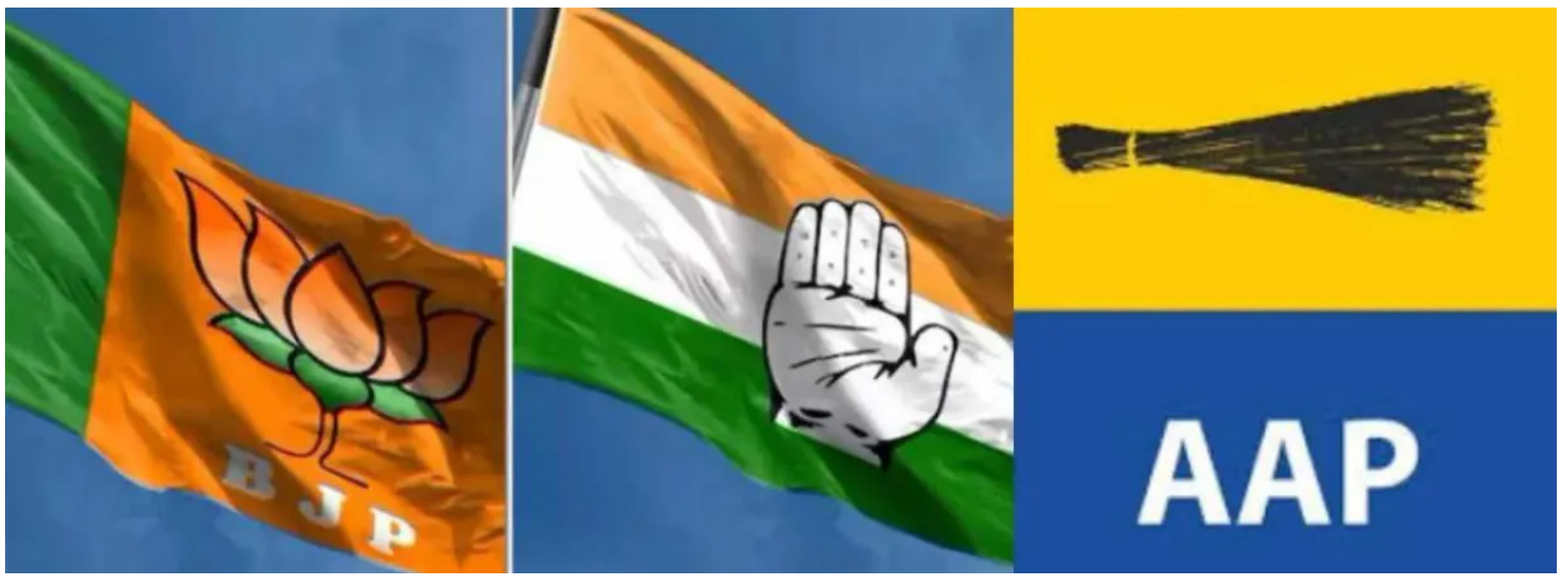

सूरत। गुजरात के सबसे बड़े शहरी निकायों में शामिल सूरत नगर निगम चुनाव 2026 के लिए चुनावी प्रचार अभियान भले ही आधिकारिक रूप से थम गया हो, लेकिन शहर का राजनीतिक माहौल अभी भी पूरी तरह गर्म है। सतही तौर पर शहर में शांति और सामान्य स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन पर्दे के पीछे राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज़ हो गई हैं और अंतिम रणनीति को अमली जामा पहनाने की कवायद जारी है।

इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि यह न केवल स्थानीय शासन की दिशा तय करेगा, बल्कि शहर के आगामी विकास मॉडल और बजट उपयोग की प्राथमिकताओं को भी प्रभावित करेगा। लगभग 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बजट वाली सूरत नगर निगम पर कब्जा जमाने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है।

शहर के प्रमुख इलाकों, खासकर वराछा-कतारगाम और लिंबायत में मुकाबला बेहद रोचक और कड़ा हो गया है। वराछा-कतारगाम जैसे पाटीदार बहुल क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं, जहां हर दल अपनी-अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। इन इलाकों में स्थानीय सामाजिक समीकरण और जातीय प्रभाव चुनावी परिणामों को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

सूरत नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच सीधा और तीखा मुकाबला है। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मुकाबला सिर्फ दलों के बीच नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर व्यक्तिगत प्रभाव और संगठनात्मक ताकत के बीच भी है।

सूत्रों के अनुसार, टिकट वितरण के बाद कई इलाकों में असंतोष और अंदरूनी मतभेद सामने आए हैं, जिसका असर अब अंतिम चरण की रणनीति में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। कई उम्मीदवारों ने खुले प्रचार के बजाय अब सीधे मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क और छोटे-छोटे समूह बैठकों पर ध्यान केंद्रित कर दिया है।

चुनाव प्रचार थमने के बाद अब डोर-टू-डोर अभियान और समाज आधारित संपर्क रणनीतियों पर जोर दिया जा रहा है। हर राजनीतिक दल अपने-अपने वोट बैंक को मजबूत करने और अंतिम समय में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के प्रयास में जुटा हुआ है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ गई है, और हर वार्ड में सूक्ष्म स्तर पर समीकरण साधने की कोशिशें जारी हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव के आखिरी 48 घंटे बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस समय की गई रणनीतिक चालें और मतदाताओं से सीधा संपर्क चुनाव परिणामों में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। कई जगहों पर मतदाता अभी भी अंतिम निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं, जिससे मुकाबला और अधिक दिलचस्प हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार संगठनात्मक स्तर पर कुछ चुनौतियां सामने आई हैं। कई क्षेत्रों में स्थानीय नेतृत्व को लेकर असंतोष की खबरें हैं, जिसके चलते कुछ स्थानों पर विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को खुद मैदान में उतरना पड़ा है। पार्टी का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि पिछले चुनावों की पकड़ को बनाए रखा जाए।

वहीं आम आदमी पार्टी में भी आंतरिक स्तर पर पूरी तरह एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। कई क्षेत्रों में उम्मीदवारों के बीच तालमेल की कमी और स्थानीय मुद्दों पर मतभेद की स्थिति देखी गई है। इसके बावजूद पार्टी अपने जनसंपर्क अभियान और नई राजनीति के संदेश को मजबूत करने में जुटी हुई है।

कांग्रेस के लिए यह चुनाव पुनर्जीवन का अवसर माना जा रहा है। पार्टी ने शहरी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए अंतिम समय तक प्रचार जारी रखा और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। हालांकि संगठनात्मक ढांचे की सीमाएं भी चुनौती बनी हुई हैं।

सूरत नगर निगम चुनाव में अब सभी दलों का ध्यान मतदान प्रक्रिया पर केंद्रित हो गया है। प्रशासन की ओर से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।

अब शहर में चुनावी शोर भले ही थम गया हो, लेकिन राजनीतिक तापमान अपने चरम पर है। हर दल अपने-अपने स्तर पर अंतिम रणनीति को मजबूत करने में लगा हुआ है। मतदाता भी अब निर्णायक भूमिका में हैं, जिनके एक-एक वोट से इस बड़े शहरी निकाय की सत्ता का भविष्य तय होगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह सूरत के विकास मॉडल, प्रशासनिक दिशा और भविष्य की शहरी राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव है। अब सभी की निगाहें मतदान और उसके बाद आने वाले परिणामों पर टिकी हैं, जो यह तय करेंगे कि किसकी रणनीति आखिरी समय में सबसे ज्यादा सफल रही।

डभोई–छोटा उदेपुर सेक्शन पर स्थित ब्रिज का सुदृढ़ीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण

पश्चिम रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा डभोई–छोटा उदेपुर सेक्शन पर स्थित ब्रिज संख्या 130 के मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इस कार्य से पुल की संरचनात्मक मजबूती और दीर्घकालिक सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह पुल नदी तल में गंभीर कटाव (scouring) के कारण प्रभावित हुआ था, जिससे पाइल कैप के नीचे पाइल्स उजागर हो गए थे, जो संरचनात्मक सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति थी ।

प्रमुख सुदृढ़ीकरण कार्य के अंतर्गत उजागर पाइल्स की सफाई व ग्राउटिंग की गई तथा 1.4 मीटर लाइनर्स की स्थापना गई। प्रत्येक पियर पर 8 (कुल 80) अतिरिक्त पाइल्स का निर्माण किया गया। पियर जैकेटिंग तथा नई पाइल्स का मौजूदा नींव से एकीकरण किया गया।

इस कार्य को अत्यंत सावधानी, उच्च गुणवत्ता मानकों एवं सुरक्षा उपायों के साथ संपन्न किया गया। पाइल्स की सफाई, निरीक्षण, ग्राउटिंग तथा इंटीग्रिटी परीक्षण जैसी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित कर संरचना की मजबूती को प्रमाणित किया गया।

इस सुदृढ़ीकरण कार्य से पुल की भार वहन क्षमता में वृद्धि हुई है तथा इस सेक्शन में ट्रेन संचालन और अधिक सुरक्षित एवं निर्बाध हो सकेगा। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे की सुरक्षा, आधुनिकीकरण और यात्री सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पश्चिम रेलवे द्वारा 25/26 अप्रैल, 2026 के दौरान उपनगरीय खंड पर दो मेजर ब्लॉक लिये जाएंगे

गर्डर लॉन्चिंग कार्य के लिए जोगेश्वरी–राम मंदिर के बीच छठी लाइन पर तथा दहिसर में ब्लॉक लिये जाएंगे

पश्चिम रेलवे द्वारा शनिवार/रविवार की मध्यरात्रि अर्थात 25/26 अप्रैल, 2026 के दौरान उपनगरीय खंड पर दो प्रमुख ब्लॉक लिये जाएंगे। ये ब्लॉक राम मंदिर और जोगेश्वरी के बीच मेट्रो लाइन-6 के स्टील गर्डरों की लॉन्चिंग तथा दहिसर में दो फुट ओवर ब्रिजों के गर्डरों की लॉन्चिंग के लिए लिये जाएंगे।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मेट्रो लाइन-6 के स्टील गर्डरों की लॉन्चिंग के लिए राम मंदिर और जोगेश्वरी के बीच एक प्रमुख ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक के अंतर्गत छठी लाइन पर 25 अप्रैल, 2026 को 22:15 बजे से 26 अप्रैल, 2026 को 08:15 बजे तक 10 घंटे कार्य किया जाएगा, जबकि सभी लाइनों पर यह ब्लॉक 26 अप्रैल, 2026 को 01:45 बजे से 04:45 बजे तक लिया जाएगा। ब्लॉक के दौरान छठी लाइन की सभी ट्रेनों को बोरीवली से अंधेरी तक अप फास्ट लाइन पर चलाया जाएगा।

उपरोक्त ब्लॉक के दौरान ही दहिसर में दो फुट ओवर ब्रिजों के गर्डरों की लॉन्चिंग के लिए एक अन्य मेजर ब्लॉक भी लिया जाएगा। दहिसर में यह ब्लॉक डाउन स्लो, अप स्लो और डाउन फास्ट लाइनों पर 26 अप्रैल, 2026 को 02:05 बजे से 04:05 बजे तक तथा अप फास्ट लाइन पर 26 अप्रैल, 2026 को 02:05 बजे से 03:05 बजे तक लिया जाएगा।

ब्लॉकों के कारण प्रभाव उपनगरीय ट्रेन सेवाएं

25 अप्रैल, 2026 को चर्चगेट से 01:00 बजे प्रस्थान करने वाली अंतिम ट्रेन अर्थात BO91055 निरस्त रहेगी। अतः चर्चगेट से विरार के लिए अंतिम ट्रेन VR91053 होगी, जो चर्चगेट से 00:50 बजे प्रस्थान करेगी।

26 अप्रैल, 2026 को विरार से पहली ट्रेन VR90018 होगी, जो 03:40 बजे प्रस्थान करेगी और गोरेगांव तक चलेगी। यह ट्रेन स्लो मोड में चलेगी।

ब्लॉक अवधि के दौरान कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी। निरस्त की गई उपनगरीय सेवाओं की विस्तृत सूची उपनगरीय खंड के सभी स्टेशनों पर उपलब्ध रहेगी।

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें

ब्लॉकों के कारण निम्नलिखित मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को रेगुलेट/रीशेड्यूल किया जाएगा:

रेगुलेट की जाने वाली ट्रेनें

24 अप्रैल, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19038 बरौनी–बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस को सूरत और विरार के बीच 1 घंटा 30 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

25 अप्रैल, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09052 भुसावल–दादर स्पेशल को नंदुरबार और विरार के बीच 30 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

25 अप्रैल, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22928 अहमदाबाद–बांद्रा टर्मिनस लोकशक्ति एक्सप्रेस को सूरत और विरार के बीच 30 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

25 अप्रैल, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 12928 एकता नगर–दादर एक्सप्रेस को सूरत और विरार के बीच 20 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

रीशेड्यूल की जाने वाली ट्रेनें

25 अप्रैल, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22946 ओखा–मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल को ओखा से 1 घंटा 15 मिनट रीशेड्यूल किया जाएगा।

25 अप्रैल, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22904 भुज–बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एसी एक्सप्रेस को भुज से 45 मिनट रीशेड्यूल किया जाएगा।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखें और तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

मेहुल टेलिकॉम की मजबूत लिस्टिंग: IPO निवेशकों को पहले ही दिन मिला करीब 10% का फायदा, बाजार में उत्साह का माहौल

नई दिल्ली। टेलीकॉम क्षेत्र की कंपनी मेहुल टेलिकॉम लिमिटेड ने शेयर बाजार में अपने पहले ही कदम में निवेशकों को खुश कर दिया है। कंपनी के आईपीओ की मजबूत मांग और सफल लिस्टिंग ने यह संकेत दिया है कि SME सेगमेंट में भी निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है। 98 के इश्यू प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर बीएसई के SME प्लेटफॉर्म पर 108 पर सूचीबद्ध हुए, जिससे निवेशकों को लगभग 10% का शुरुआती लाभ मिला। लिस्टिंग के तुरंत बाद शेयर में हल्का उतार-चढ़ाव भी देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में शेयर 109.90 तक पहुंच गया, लेकिन मुनाफावसूली के चलते यह थोड़ा फिसलकर 104 के स्तर पर भी आया। हालांकि, सुबह 10:45 बजे तक यह फिर से संभलते हुए 107.75 के आसपास कारोबार करता दिखा, जो अभी भी इश्यू प्राइस के मुकाबले लगभग 9.95% की बढ़त को दर्शाता है।

मेहुल टेलिकॉम लिमिटेड का 88.02 करोड़ का आईपीओ 17 से 21 अप्रैल के बीच खुला था और इसे निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। कुल मिलाकर यह इश्यू 44.91 गुना सब्सक्राइब हुआ, जो बाजार में कंपनी के प्रति मजबूत भरोसे को दर्शाता है। इसमें संस्थागत निवेशकों (QIB) का सब्सक्रिप्शन 32.5 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) का 79.38 गुना और खुदरा निवेशकों का 37.41 गुना रहा, जो बेहद मजबूत मांग को दर्शाता है। इस आईपीओ के तहत 10 फेस वैल्यू वाले 28,29,600 नए शेयर जारी किए गए थे। कंपनी ने इस इश्यू से जुटाई गई राशि का उपयोग मुख्य रूप से वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए करने की योजना बनाई है। इससे कंपनी के संचालन और विस्तार योजनाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वित्तीय प्रदर्शन के मोर्चे पर भी मेहुल टेलिकॉम लिमिटेड ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में जहां कंपनी मामूली घाटे में थी, वहीं 2024-25 में यह 5.74 करोड़ के शुद्ध लाभ में बदल गई। चालू वित्त वर्ष में कंपनी का लाभ बढ़कर 7.07 करोड़ तक पहुंच गया है, जो इसके बेहतर संचालन और बढ़ती मांग का संकेत है। हालांकि इसी दौरान कंपनी के कर्ज में भी हल्की बढ़ोतरी देखी गई है। 2023-24 में लगभग कर्जमुक्त स्थिति से आगे बढ़ते हुए 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) में कंपनी पर 3.72 करोड़ का कर्ज दर्ज हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़ोतरी कंपनी के विस्तार और कार्यशील पूंजी की जरूरतों के कारण हो सकती है।

दूसरी ओर, कंपनी की नेटवर्थ में मजबूत उछाल देखने को मिला है। 2023-24 में यह केवल 9 लाख थी, जो 2024-25 में बढ़कर 17.10 करोड़ हो गई और वर्तमान वित्त वर्ष में यह 24.18 करोड़ तक पहुंच गई है। इसी तरह EBITDA में भी तेज वृद्धि हुई है, जो 3.04 करोड़ से बढ़कर 9.71 करोड़ तक पहुंच गया है। यह आंकड़े कंपनी की ऑपरेशनल दक्षता और बिजनेस ग्रोथ की मजबूत तस्वीर पेश करते हैं।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि SME सेगमेंट में मेहुल टेलिकॉम लिमिटेड जैसी कंपनियों की सफल लिस्टिंग यह संकेत देती है कि छोटे और मझोले स्तर की कंपनियों में निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। हालांकि, वे यह भी सलाह देते हैं कि इस तरह के स्टॉक्स में उतार-चढ़ाव अधिक होता है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहकर निर्णय लेना चाहिए।

फिलहाल, आईपीओ निवेशकों के लिए यह लिस्टिंग एक सकारात्मक शुरुआत मानी जा रही है, जहां उन्हें पहले ही दिन लगभग 10% का लाभ मिला है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बाजार में कंपनी अपनी यह गति कितनी देर तक बनाए रख पाती है।

भावनगर टर्मिनस–शहीद कप्तान तुषार महाजन एक्सप्रेस की सेवाएं पुनः बहाल

यात्रियों की सुविधा एवं बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व में निरस्त की गई ट्रेन संख्या 19107/19108 भावनगर टर्मिनस–शहीद कप्तान तुषार महाजन एक्सप्रेस की सेवाओं को पुनः बहाल (Restoration) करने का निर्णय लिया गया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त ट्रेन के लिए आरक्षण (Booking) 24 अप्रैल, 2026 (शुक्रवार) से IRCTC की वेबसाइट तथा पीआरएस (PRS) काउंटरों के माध्यम से प्रारंभ किया जा चुका है। यह ट्रेन 07 जून, 2026 से आगे की यात्रा तिथियों के लिए उपलब्ध रहेगी।

उल्लेखनीय है कि परिचालन कारणों से

इस ट्रेन का संचालन पूर्व में निर्धारित अवधि तक स्थगित रखा गया था। अब यात्रियों की बढ़ती मांग एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इसकी सेवाओं को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आवागमन में बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश शर्मा ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पूर्व ट्रेनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें तथा इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

अहमदाबाद मंडल में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर का निर्माण, रेल संचालन में तकनीकी उत्कर्ष की ओर एक महत्वपूर्ण पहल

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा स्टेट-ऑफ-द-आर्ट इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जो जून 2026 तक कार्यरत हो जाएगा। लगभग 24,500 वर्ग फुट में विस्तृत यह अत्याधुनिक परिसर उत्तरी गुजरात क्षेत्र में रेल संचालन का "केंद्रीय तंत्र (Nerve Centre)" होगा। वर्ष 2003 में स्थापना के पश्चात अहमदाबाद मंडल ने तीव्र प्रगति दर्ज की है। माल लदान 9.38 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 51 मिलियन टन तक पहुँच गया है, जो पाँच गुना से अधिक वृद्धि को दर्शाता है। इस बढ़ते परिचालन को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु विभिन्न कार्यालयों की नियंत्रण गतिविधियों को अब एक ही छत के नीचे केंद्रीकृत किया जा रहा है।

यह अत्याधुनिक नियंत्रण परिसर विभिन्न विभागों के समन्वित, त्वरित एवं प्रभावी संचालन हेतु डिज़ाइन किया गया है:

उन्नत डिजिटल निगरानी (Next-Gen Monitoring): 1,350 रूट किलोमीटर क्षेत्र की रियल-टाइम, उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉनिटरिंग हेतु विशाल वीडियो डिस्प्ले यूनिट (VDU) वॉल, जो त्वरित निर्णय-निर्धारण में सहायक होगी।

समेकित परिचालन प्रणाली (Integrated Operations System): फ्रेट एवं कोचिंग कंट्रोल, सिग्नल एवं दूरसंचार (S&T), इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन तथा क्रू प्रबंधन का एकीकृत संचालन किया जाएगा।

सुरक्षा एवं संरक्षा सुदृढ़ीकरण (Safety & Security Enhancement): रेलवे सुरक्षा बल (RPF) नियंत्रण कक्ष, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ एवं कैरिज एवं वैगन (C&W) गतिविधियाँ भी इस परिसर में समाहित की जाएँगी। यात्री सेवा सुदृढ़ीकरण (Passenger Service Enhancement): 'रेल मदद' (Rail Madad) शिकायत निवारण तंत्र एवं NTES (National Train Enquiry System) के साथ प्रत्यक्ष एकीकरण, जिससे यात्रियों को सटीक एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

इस एकीकृत नियंत्रण परिसर के क्रियान्वयन से निम्नलिखित बहुआयामी लाभ प्राप्त होंगे:

समयपालन में उच्च स्तर की सटीकता (High Precision in Punctuality): प्रतिदिन संचालित 130+ कोचिंग ट्रेनों एवं 160+ मालगाड़ियों के संचालन में सटीक योजना एवं समयपालन सुनिश्चित होगा।

संचालन प्रक्रियाओं का अनुकूलन (Operational Process Optimization): लोको परिवर्तन, जल आपूर्ति, पार्सल प्रबंधन एवं क्रू तैनाती में समयबद्धता एवं दक्षता में वृद्धि आएगी।

रियल-टाइम डेटा आधारित सेवाएँ Real-Time Data Driven Services): रियल-टाइम डेटा प्रवाह के माध्यम से यात्रियों को पारदर्शी एवं विश्वसनीय सेवाएँ प्राप्त होंगी।

यह इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर केवल एक भवन नहीं, बल्कि उन्नत तकनीक एवं समेकित कार्यप्रणाली का प्रतीक है। यह केंद्र 24×7 संचालित रहेगा। कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे आधुनिक एवं कार्यक्षम कार्यस्थल के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही, कर्मचारियों के लिए कैंटीन, विश्राम कक्ष, मिनी बोर्ड रूम एवं समर्पित पार्किंग जैसी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, ताकि कार्य निष्पादन अधिक सुगम, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी हो सके।

यात्री भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में अस्थायी अतिरिक्त कोचों की व्यवस्था

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की बढ़ती मांग एवं अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए दो जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 20486/20485 साबरमती–जोधपुर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 20486 (साबरमती–जोधपुर) में दिनांक 03 मई से 02 जून 2026 तक तथा

ट्रेन संख्या 20485 (जोधपुर–साबरमती) में दिनांक 01 मई से 31 मई 2026 तक

एक अतिरिक्त 3-टियर एसी तथा दो स्लीपर श्रेणी के कोच अस्थायी रूप से जोड़े जाएंगे।

2. ट्रेन संख्या 20492/20491 साबरमती–जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 20492 (साबरमती–जैसलमेर) में दिनांक 01 मई से 31 मई 2026 तक तथा

ट्रेन संख्या 20491 (जैसलमेर–साबरमती) में दिनांक 02 मई से 01 जून 2026 तक

एक अतिरिक्त 3-टियर एसी तथा दो स्लीपर श्रेणी के कोच अस्थायी रूप से जोड़े जाएंगे।

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

संख्या- W/623/5/1/NIT | **ई-टेंडरिंग नोटिस** | दिनांक: 24.04.2026

मण्डल रेल प्रबंधक/मण्डल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा) पश्चिम रेलवे रतलाम की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये "खुली निविदा" ई-निविदा के माध्यम से वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित करते हैं। विवरण इस प्रकार है-

क्र. सं.: 1. ई-टेंडरिंग: RTM-2026-27-38. कार्य का नाम: Godhra-Nagda Section:- Regrading of LC approaches, improvement to road surfaces, providing speed breakers and other misc repair works, at LCs 8 Nos. **अनुमानित लागत**: रु 1,92,54,221.13. **बयाना राशि**: रु 3,85,100/-. **कार्य समापन अवधि**: 18 Months. **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि**: 21.04.2026. **निविदा खुलने की तिथि**: 13.05.2026.

क्र. सं.: 2. ई-टेंडरिंग: RTM-2026-27-39. कार्य का नाम: GDA-NAD Section:- Providing 20 units type-II Staff quarters at Dahod and 10 units type-II Staff quarters at Piplod in lieu of old Dilapidated quarters. **अनुमानित लागत**: रु 6,31,61,093.56. **बयाना राशि**: रु 12,63,200/-. **कार्य समापन अवधि**: 18 Months. **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि**: 20.04.2026. **निविदा खुलने की तिथि**: 13.05.2026.

क्र. सं.: 3. ई-टेंडरिंग: RTM-2026-27-40. कार्य का नाम: Dahod(LCW):-Providing of 20 bed barrack at DHD Loco workshop. **अनुमानित लागत**: रु 1,78,77,494.72. **बयाना राशि**: रु 3,57,600/-. **कार्य समापन अवधि**: 18 Months. **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि**: 20.04.2026. **निविदा खुलने की तिथि**: 13.05.2026.

क्र. सं.: 4. ई-टेंडरिंग: RTM-2026-27-41. कार्य का नाम: RTM Division - Provision of PF ends connecting pathway at 13 stations. (Divyangjan facilities). **अनुमानित लागत**: रु 69,59,384.05. **बयाना राशि**: रु 1,39,200/-. **कार्य समापन अवधि**: 12 Months. **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि**: 21.04.2026. **निविदा खुलने की तिथि**: 13.05.2026.

ऊपर के सभी टेंडर के लिए अनुमानित मात्रा: As per tender schedule. विस्तृत निविदा सूचना, अहाता शर्तें एवं अन्य शर्तें वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। AK/16

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: X.com/WesternRly

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2016 के भारतीय नोटबंदी मामले में आदेश जारी कर आरबीआई को पुराने नोट बदलने का निर्देश दिया है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की गई थी। अचानक हुई नोटबंदी के कारण कई लोग समय सीमा के भीतर पुराने 500 रुपये के नोट भी नहीं बदलवा पाए। इसी समय सीमा के तहत, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को आदेश दिया कि नोटबंदी की घोषणा के बाद पुलिस द्वारा जब्त किए गए 2 लाख रुपये के पुराने 500 रुपये के नोट बदले जाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवेदक को उस गलती के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उसकी नहीं है। 8 नवंबर 2016 को अचानक हुई नोटबंदी के समय, आवेदक गिरीश मलानी 1 दिसंबर 2016 को 2 लाख रुपये नकद लेकर यात्रा कर रहे थे। तब नगर निगम चुनावों के संबंध में एहतियात के तौर पर पुलिस गश्ती दल ने यह पैसा जब्त कर लिया था। इसके बाद, आयकर विभाग ने जांच के दौरान स्वीकार किया कि यह पैसा वैध था। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया के चलते 31 दिसंबर 2016 को आवेदक को राशि वापस कर दी गई। इस दौरान पुराने नोट जमा करने की अंतिम तिथि बीत चुकी थी, इसलिए आरबीआई ने नोट बदलने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता की पीठ ने कहा कि चूंकि करेंसी नोट पुलिस हिरासत में थे, इसलिए आवेदक के पास उन्हें जमा करने का कोई विकल्प नहीं था। अदालत ने आरबीआई के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि नोटों के सीरियल नंबर दर्ज नहीं किए गए थे। अदालत ने कहा कि कानूनी देरी के कारण आवेदक को नुकसान उठाना उचित नहीं है। उच्च न्यायालय ने गिरीश मलानी को एक सप्ताह के भीतर पुराने नोट आरबीआई के पास जमा करने को कहा है और रिजर्व बैंक को 7 सप्ताह के भीतर उनका सत्यापन करने और उसी राशि के वैध नोट जारी करने का आदेश दिया है।

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

ई-निविदा सूचना

वरिष्ठ मंडल विद्युत् इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित करते हैं: **निविदा क्रमांक: EL/TRD/58/2026-27/03, दिनांक: 20.04.2026. कार्य का नाम**: TRD Work in connection with extension of machine Siding and dead ends of Line Number 1 to stable full length trains at Vikaram nagar Station in connection of Simhastha 2028. **अनुमानित लागत**: रु 2,22,80,002.50. **बयाना राशि**: रु 4,45,600/-. **समापन अवधि**: 18 Months. **निविदा दस्तावेज़ की राशि**: Nil. **ऑनलाइन बिडिंग बंद होने की दिनांक एवं समय**: 18.05.2026 at 15:00 hrs. **ऑफर की वैधता**: 60 days from the date of opening. अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखा जा सकता है। AK/15

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेल्वे

एयरलेस स्प्रे पेईन्टींग

सहायक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, EMU वर्कशॉप, महालक्ष्मी, मुंबई - 400013, टेंडर नोटिस संख्या: EL90-MX- 2025-26-01-MR, दिनांक 20.04.2026 आमंत्रित करते हैं। कार्य का नाम और स्थान: "EMU वर्कशॉप महालक्ष्मी में EMU / MEMU कोचों की बाहरी सतह और अंदरूनी FRP पेनलों पर एयरलेस स्प्रे पेईन्टींग, साथ ही लेटरिंग और स्टेंसिलिंग का काम" अनुमानित लागत: ₹ 10,79,08,861.86 जमा की जाने वाली बिड सिक्योरिटी (E M D): ₹ 21,58,200/- । ऑनलाइन सबमिशन और ई-बिड्स व ई-टेंडर्स खोलने की अंतिम तिथि और समय: दि.15.05.2026 को 15:00 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 0021

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

सूरत में 26 अप्रैल को लोकतंत्र का बड़ा पर्व: लोकल बॉडी चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार, 24 लाख से अधिक मतदाता करेंगे फैसला, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम

सूरत। गुजरात के प्रमुख औद्योगिक और शहरी केंद्र सूरत में लोकतंत्र का बड़ा उत्सव 26 अप्रैल, रविवार को आयोजित होने जा रहा है, जब शहर और जिले में लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट चुनावों के लिए मतदान कराया जाएगा। इस चुनाव में नगर निगम, नगरपालिकाओं, जिला पंचायत और तालुका पंचायत की विभिन्न सीटों पर मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। पूरा प्रशासनिक तंत्र इस महापर्व को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गया है।

इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव से पहले की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सूरत में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें की गईं, ताकि मतदान के दिन किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या गड़बड़ी की संभावना को समाप्त किया जा सके।

डॉ. सौरभ पारधी, जो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, ने बताया कि इस बार चुनाव को पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हर स्तर पर सख्त व्यवस्था की गई है। उनके साथ अनुपमसिंह गहलोत (पुलिस कमिश्नर) और राजेश गढ़िया (जिला पुलिस प्रमुख) ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि सुरक्षा से लेकर मतदान केंद्रों की व्यवस्था तक हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इस बार सूरत नगर निगम के 30 वार्डों में कुल 483 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं चार नगरपालिकाओं में 224 उम्मीदवार, जिला पंचायत की 88 सीटों पर और तालुका पंचायत की 513 सीटों पर प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह चुनाव न केवल स्थानीय प्रशासन की दिशा तय करेगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी विकास की भविष्य की रूपरेखा भी निर्धारित करेगा।

इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूरत नगर निगम क्षेत्र में ही 24.76 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा नगरपालिकाओं, जिला पंचायत और तालुका पंचायत क्षेत्रों को मिलाकर लाखों अन्य मतदाता भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। यह आंकड़ा इस चुनाव को गुजरात के सबसे बड़े स्थानीय चुनावों में से एक बनाता है।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। जिला पंचायत की 36 सीटों में से 4 सीटें पहले ही निर्विरोध घोषित हो चुकी हैं, जबकि शेष 32 सीटों पर मतदान होगा। इसी प्रकार नगरपालिकाओं की 16 सीटें और तालुका पंचायत की 21

सीटें भी बिना मुकाबले के निर्विरोध घोषित की गई हैं। यह स्थिति कई जगहों पर राजनीतिक सहमति और स्थानीय समीकरणों को दर्शाती है।

मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पूरे शहर और जिले में कुल 2,610 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था, मेडिकल किट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

EVM मशीनों की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी मशीनों की सीलिंग पूरी कर उन्हें सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर उपयोग के लिए रिजर्व मशीनें भी तैयार रखी गई हैं, ताकि मतदान प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। शहर में 9,500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो मतदान के दिन विभिन्न केंद्रों पर सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इन पुलिसकर्मियों की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष टीम नियुक्त की गई है, जो लगातार स्थिति पर नजर रखेगी।

इसके अलावा 565 वाहनों से पेट्रोलिंग की जाएगी और 50 विशेष टीमें, क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) तथा चेकपोस्ट के माध्यम से पूरे शहर में सतर्क निगरानी रखी जाएगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई दल को तैयार रखा गया है।

प्रशासन ने तकनीक का भी व्यापक उपयोग किया है। मतदान केंद्रों और संवेदनशील क्षेत्रों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जबकि कुछ स्थानों पर बॉडी-वॉर्न कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही एक केंद्रीय कंट्रोल रूम से पूरे चुनावी प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जाएगी।

चुनाव से पहले ही प्रशासन ने असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करते हुए हजारों लोगों पर निवारक कदम उठाए हैं। कई संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. सौरभ पारधी ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे बिना किसी डर या दबाव के मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हर वोट महत्वपूर्ण है और नागरिकों की भागीदारी ही मजबूत स्थानीय शासन की नींव रखती है।

अनुपमसिंह गहलोत ने कहा कि पुलिस बल पूरी तरह तैयार है और हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाएगा।

राजेश गढ़िया ने बताया कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता को रोकने के लिए विशेष निगरानी टीमों को तैनात किया गया है और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त बल लगाया गया है।

इस पूरे चुनावी माहौल में सूरत शहर एक बार फिर लोकतंत्र के उत्सव का साक्षी बनने जा रहा है, जहां लाखों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर स्थानीय शासन की दिशा तय करेंगे। प्रशासन का दावा है कि यह चुनाव अब तक के सबसे सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित स्थानीय चुनावों में से एक होगा।

मतगणना 28 अप्रैल को की जाएगी, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि सूरत के मतदाताओं ने किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनकर स्थानीय शासन की जिम्मेदारी सौंपी है।

पारुल यूनिवर्सिटी के 234 छात्रों को टीसीएस में मिला बड़ा अवसर, कैंपस प्लेसमेंट ने रचा नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कैंपस रिक्रूटमेंट के तहत पारुल यूनिवर्सिटी के वर्ष 2026 बैच के 234 छात्रों को आकर्षक सैलरी पैकेज के साथ नौकरी का ऑफर दिया है। इस सफलता ने न केवल विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूत किया है, बल्कि छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा भी तय की है।

कैंपस प्लेसमेंट के दौरान चयनित छात्रों को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में अवसर प्रदान किए गए हैं, जिनमें एमसीए, एमएससी आईटी, बीटेक सीएसई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक जैसे आधुनिक कोर्स शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में उद्योग की बढ़ती मांग को देखते हुए यह चयन छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया में छात्रों को 3.6 लाख से लेकर 9 लाख रुपये तक का वार्षिक पैकेज ऑफर किया गया है। विशेष रूप से बीटेक सीएसई के छात्र अभिषेक गुप्ता, कोय्या साई श्रीवास्तव और शैलेंद्र सोनी को सर्वाधिक 9 लाख का वार्षिक पैकेज मिला है, जो उनकी तकनीकी दक्षता और प्रदर्शन का प्रमाण है।

पारुल यूनिवर्सिटी में यह प्लेसमेंट

केवल एक विभाग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विभिन्न संकायों के छात्रों ने इसमें भाग लेकर सफलता हासिल की है। विश्वविद्यालय के अनुसार यह उपलब्धि शैक्षणिक कार्यक्रमों और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच मजबूत तालमेल का परिणाम है।

इसके साथ ही यह भी जानकारी सामने आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी 108 छात्रों को नौकरी के प्रस्ताव दिए हैं। वहीं, केपजेमिनी जैसी बड़ी आईटी कंपनी ने 157 छात्रों को रोजगार का अवसर दिया है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, कॉग्निजेंट, एलटीआई माइंडट्री और हेक्सावेयर जैसी वैश्विक कंपनियों ने भी छात्रों को आकर्षक पैकेज के साथ चयनित किया है, जिससे विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट रिकॉर्ड को नई ऊंचाई मिली है।

अब तक पारुल यूनिवर्सिटी के वर्ष 2026 बैच के 3,500 से अधिक छात्रों को विभिन्न कंपनियों में नौकरी मिल चुकी है। इसके अलावा 23 छात्रों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में विशेष अवसर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 छात्रों को लिंक्डइन द्वारा प्रोफेशनल कोचिंग और मेंटरशिप भी दी गई है। यह कदम छात्रों के करियर विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें तैयार करने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह सफलता उनके उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रम और मजबूत प्रशिक्षण प्रणाली का परिणाम है। छात्रों को केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक कौशल, समस्या समाधान क्षमता और कॉर्पोरेट वातावरण में ढलने की योग्यता भी विकसित की जाती है।

देवांशु पटेल ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि 234 छात्रों के सपनों के साकार होने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह सफलता वर्षों की मेहनत, समर्पण और सही मार्गदर्शन का परिणाम है।

उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण प्रणाली ने छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया है।

पारुल यूनिवर्सिटी की यह उपलब्धि यह दर्शाती है कि यदि शिक्षा और उद्योग के बीच सही तालमेल बनाया जाए तो छात्रों को बेहतरीन करियर अवसर मिल सकते हैं। इस प्लेसमेंट ड्राइव ने एक बार फिर साबित किया है कि भारतीय युवा वैश्विक आईटी सेक्टर में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं।

कुल मिलाकर, यह कैंपस प्लेसमेंट न केवल छात्रों के लिए सफलता का प्रतीक है, बल्कि शिक्षा जगत में एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है, जो आने वाले समय में अन्य संस्थानों के लिए भी एक मॉडल साबित हो सकता है।

अडानी ने संपत्ति के मामले में रचा नया रिकॉर्ड, 106 अरब डॉलर के साथ फिर $100 अरब क्लब में वापसी

नई दिल्ली। वैश्विक शेयर बाजारों में जारी उतार-चढ़ाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज गौतम अडानी की संपत्ति में एक बार फिर जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर्स इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार उनकी कुल नेटवर्थ 7.16 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 106 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जिसके साथ वे एक बार फिर '$100 अरब क्लब' में शामिल हो गए हैं।

इस बढ़त ने न केवल वैश्विक निवेशकों का ध्यान खींचा है, बल्कि अमीरों की वैश्विक सूची में भी बड़ा बदलाव किया है। इस उछाल के बाद गौतम अडानी अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है, जो अब 104 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 18वें स्थान पर खिसक गए हैं।

यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक बाजारों में तकनीकी शेयरों और ऊर्जा क्षेत्र में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक गौतम अडानी की संपत्ति में कुल 21.4 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो उनके समूह के विभिन्न क्षेत्रों—इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और पोर्ट सेक्टर—में मजबूत प्रदर्शन का संकेत देती है।

वहीं दूसरी ओर बिल गेट्स की संपत्ति में इसी अवधि के दौरान 12.7 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण उनके निवेश पोर्टफोलियो में आए बदलाव और परोपकारी दान गतिविधियों में बढ़ोतरी को माना जा रहा है।

भारतीय बाजार के एक और बड़े नाम मुकेश अंबानी की संपत्ति में भी गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को उनकी नेटवर्थ में 1.11 अरब डॉलर की कमी आई, जिसके बाद उनकी कुल संपत्ति 90.2 अरब डॉलर रह गई। इसके साथ ही वे वैश्विक सूची में 20वें स्थान पर हैं।

रिपोर्ट बताती है कि इस वर्ष अब तक उनकी संपत्ति में कुल 17.5 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है, जो पेट्रोकेमिकल और टेलीकॉम सेक्टर में दबाव को दर्शाता है।

हालांकि भारतीय उद्योगपतियों की स्थिति में उतार-चढ़ाव जारी है, लेकिन वैश्विक स्तर पर तकनीकी क्षेत्र के दिग्गज अभी भी शीर्ष पर बने हुए हैं। सूची में पहले स्थान पर एलन मस्क हैं, जिनकी संपत्ति 645 अरब डॉलर है। हालांकि उनकी नेटवर्थ में भी 9.89 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है, फिर भी वे मजबूती से शीर्ष पर बने हुए हैं।

इसके बाद दूसरे स्थान पर लैरी पेज (289 अरब डॉलर), तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस (274 अरब डॉलर) और चौथे स्थान पर सर्गेई ब्रिन (269 अरब डॉलर) शामिल हैं। इन तीनों दिग्गजों का प्रभाव मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर रहा है।

शीर्ष-10 सूची में आगे मार्क जुकरबर्ग (233 अरब डॉलर), लैरी एलिसन (227 अरब डॉलर), माइकल डेल (179 अरब डॉलर), जेंसन हुआंग (165 अरब डॉलर), बर्नार्ड अरनॉल्ट (160 अरब डॉलर) और जिम वॉल्टन (157 अरब डॉलर) शामिल हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में यह उतार-चढ़ाव केवल व्यक्तिगत कंपनियों के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीतियों, ब्याज दरों, टेक सेक्टर की ग्रोथ और ऊर्जा बाजार की अस्थिरता का भी बड़ा प्रभाव होता है। इसी वजह से कभी किसी की संपत्ति तेजी से बढ़ती है तो कभी अचानक गिरावट भी देखने को मिलती है।

गौतम अडानी की इस वापसी को भारतीय कॉरपोरेट जगत के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उनके समूह की कंपनियों में हाल के महीनों में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जिससे शेयरों में तेजी आई है और नेटवर्थ में उछाल दर्ज हुआ है।

आर्थिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि वैश्विक बाजार में जब भी बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तेजी आती है, तो अडानी समूह जैसी कंपनियों को सीधा लाभ मिलता है। यही कारण है कि उनकी संपत्ति में यह तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है।

कुल मिलाकर, यह बदलाव सिर्फ एक रैंकिंग अपडेट नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन में हो रहे बड़े बदलावों का संकेत है। जहां एक तरफ गौतम अडानी फिर से 100 अरब डॉलर क्लब में लौटकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक टेक दिग्गज अभी भी शीर्ष स्थानों पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं।

104 वर्ष की उम्र में लोकतंत्र की मिसाल बनीं 'सविता बा': हर चुनाव में मतदान कर देती हैं प्रेरणा का संदेश

वडोदरा। उम्र भले ही 104 वर्ष की हो गई हो, लेकिन लोकतंत्र के प्रति जुनून और जिम्मेदारी आज भी उतनी ही मजबूत है। गुजरात के वडोदरा शहर की सविता मंगलदास शाह, जिन्हें सभी स्नेहपूर्वक 'सविता बा' कहकर पुकारते हैं, एक बार फिर वर्ष 2026 के नगर निगम चुनाव में मतदान करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी यह प्रतिबद्धता न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई है।

सविता मंगलदास शाह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने जीवन में आज तक कोई भी चुनाव नहीं छोड़ा है। चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो, उन्होंने हमेशा मतदान केंद्र तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस वर्ष भी उन्होंने अपने परिवार के साथ मतदान करने का संकल्प लिया है और अन्य नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग अवश्य करें।

तेज स्मरण शक्ति, मुस्कुराता चेहरा और सरल स्वभाव वाली सविता मंगलदास शाह अपने आसपास के लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनकी जीवनशैली बेहद सादगीपूर्ण है, जिसमें नियमित दिनचर्या, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और प्रार्थना शामिल है। उनकी यही दिनचर्या उन्हें मानसिक रूप से मजबूत और सकारात्मक बनाए रखती है।

उनका जीवन केवल एक लंबी उम्र की

कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के इतिहास से जुड़ी एक जीवंत गाथा भी है। उन्होंने अपने बचपन के दिनों में एक स्कूल कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी से मिलने का अवसर प्राप्त किया था। यह अनुभव उनके जीवन की सबसे मूल्यवान स्मृतियों में से एक माना जाता है।

सविता मंगलदास शाह ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा को गुजरते हुए भी देखा था, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। इसके अलावा उन्होंने प्रसिद्ध गोल्डन ब्रिज के उद्घाटन समारोह में भी भाग लिया था, जो उस समय एक बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जाती थी। उनके जीवन में ऐसे कई अनुभव हैं जो उन्हें देश के इतिहास से सीधे जोड़ते हैं।

आज भी, इतनी उम्र में भी उनकी सक्रियता कम नहीं हुई है। वे अपने परिवार के साथ वडोदरा के मंजलपुर क्षेत्र में अपनी बेटी योगिनी शाह के साथ रहती हैं। परिवार में उनकी बहू मेघना शाह भी नियमित रूप से उनसे मिलने आती हैं। उनका परिवार उन्हें केवल एक बुजुर्ग सदस्य नहीं, बल्कि प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखता है।

सविता मंगलदास शाह का मानना है कि लोकतंत्र की असली ताकत नागरिकों के वोट में होती है। वे हमेशा लोगों को यह संदेश देती हैं कि मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। यदि हर नागरिक अपने मताधिकार का सही उपयोग करे, तो देश और समाज दोनों की दिशा बदल सकती है।

उनकी यही सोच उन्हें विशेष बनाती है। 104 वर्ष की उम्र में भी उनका उत्साह किसी युवा से कम नहीं है। मतदान के प्रति उनका यह समर्पण यह दर्शाता है कि लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवंत भावना है, जिसे हर पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए।

स्थानीय लोग भी सविता मंगलदास शाह को एक प्रेरणास्रोत मानते हैं। कई युवा उनसे मिलने आते हैं और उनके जीवन से सीख लेने की कोशिश करते हैं। उनका जीवन यह साबित करता है कि यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती।

आने वाले नगर निगम चुनाव में भी सविता मंगलदास शाह अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर जाएंगी और एक बार फिर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगी। उनकी यह यात्रा न केवल व्यक्तिगत कर्तव्य का उदाहरण है, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक संदेश भी है—कि हर नागरिक को बिना किसी रुकावट के अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए।

उनकी कहानी यह सिखाती है कि लोकतंत्र की ताकत केवल सरकारों में नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों में होती है। और जब ऐसे नागरिक 104 वर्ष की उम्र में भी अपने अधिकार को निभाने के लिए तत्पर हों, तो वह पूरे समाज के लिए एक जीवंत प्रेरणा बन जाते हैं।

लखीमपुर खीरी के पास जहरीला खाना खाने से 25 गिद्धों की मौत, वन विभाग अलर्ट पर

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के पास समरिया गांव के एक खेत में 25 गिद्धों के शव मिले हैं। ग्रामीणों ने एक कुत्ते को जहरीले कीटनाशकों से सना चावल खिलाकर मार डाला था क्योंकि वह बार-बार बकरियों पर हमला कर रहा था। जहरीला चावल खाने के बाद कुत्ते की मौत हो गई।

खुले मैदान में मृत कुत्ते को देखकर गिद्धों का एक झुंड वहाँ जमा हो गया। ग्रामीण भी इतने सारे गिद्धों को आकाश से उतरते देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। लेकिन यह प्रसन्नता क्षणिक थी। कुत्ते का मांस जहर से दूषित हो गया था और मांस खाने वाले गिद्ध भी कुछ ही मिनटों में जहर से प्रभावित होने लगे। एक के बाद एक लगभग 25 गिद्ध मौके पर ही मर गए। यह क्षेत्र दुधवा बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मृत गिद्धों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पांच अन्य गिद्ध अभी भी बीमार हैं।

डभोई–छोटा उदेपुर रेल सेक्शन पर ब्रिज संख्या 130 का सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण, ट्रेन संचालन होगा और सुरक्षित व सुगम

वडोदरा। पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले डभोई–छोटा उदेपुर रेल सेक्शन पर स्थित ब्रिज संख्या 130 के महत्वपूर्ण मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस कार्य के पूरा होने के बाद इस सेक्शन में रेल संचालन की सुरक्षा और संरचनात्मक स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है।

यह कार्य पश्चिम रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया गया, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकों और उच्च सुरक्षा मानकों का पालन किया गया। इस पूरे अभियान की निगरानी वडोदरा मंडल के अधिकारियों द्वारा की गई, ताकि किसी भी स्तर पर संरचना की मजबूती से समझौता न हो।

जानकारी के अनुसार, अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि ब्रिज संख्या 130 नदी तल में गंभीर कटाव (scouring) के कारण प्रभावित हो गया था। इस कटाव के चलते पाइल कैप के नीचे स्थित पाइल्स उजागर हो गए थे, जिससे पुल की संरचनात्मक सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। यदि समय रहते इसका सुदृढ़ीकरण नहीं किया जाता, तो भविष्य में रेल संचालन पर बड़ा जोखिम उत्पन्न हो सकता था।

इसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने तुरंत मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्य शुरू किया। इस कार्य के अंतर्गत सबसे पहले उजागर पाइल्स की गहन सफाई की गई और उसके बाद विशेष ग्राउटिंग तकनीक का उपयोग कर संरचना को मजबूत किया गया। इसके साथ ही 1.4 मीटर लंबी

लाइनर्स की स्थापना की गई, जिससे नींव को अतिरिक्त मजबूती प्रदान की जा सके। इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रत्येक पियर पर 8 अतिरिक्त पाइल्स का निर्माण था। कुल मिलाकर 80 नई पाइल्स का निर्माण किया गया, जिससे पुल की भार वहन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा पियर जैकेटिंग की प्रक्रिया अपनाकर पुरानी और नई संरचनाओं को एकीकृत किया गया, ताकि पुल एक मजबूत और एकीकृत ढांचे के रूप में कार्य कर सके।

पूरे कार्य को अत्यंत सावधानी और तकनीकी दक्षता के साथ पूरा किया गया। इंजीनियरिंग टीम ने पाइल्स की सफाई, निरीक्षण, ग्राउटिंग और इंटीग्रिटी टेस्टिंग जैसी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को अंजाम दिया। इन परीक्षणों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि पुल अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और सुरक्षित है।

पश्चिम रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस सुदृढ़ीकरण कार्य से न केवल पुल की संरचनात्मक क्षमता बढ़ी है, बल्कि इस सेक्शन पर ट्रेन संचालन भी अधिक सुरक्षित और निर्बाध हो सकेगा। अब भारी बारिश या नदी के बढ़े जलस्तर जैसी स्थितियों में भी इस पुल की स्थिरता पर कोई खतरा नहीं रहेगा।

डभोई–छोटा उदेपुर सेक्शन स्थानीय और दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में इस ब्रिज का मजबूत होना न केवल रेलवे संचालन के लिए बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और समयबद्ध ट्रेन संचालन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।

रेलवे इंजीनियरों का कहना है कि यह परियोजना भारतीय रेलवे की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। पुराने और कमजोर ढांचों की पहचान कर उन्हें आधुनिक तकनीक के माध्यम से मजबूत करना रेलवे की लगातार चल रही प्रक्रिया का हिस्सा है।

पश्चिम रेलवे द्वारा किए गए इस कार्य को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि इससे न केवल मौजूदा संरचना को सुरक्षित किया गया है, बल्कि भविष्य में संभावित दुर्घटनाओं की संभावना को भी काफी हद तक कम किया गया है।

स्थानीय स्तर पर भी इस कार्य को लेकर संतोष व्यक्त किया जा रहा है। यात्रियों और कर्मचारियों का मानना है कि इस तरह के सुधार कार्यों से रेलवे व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होता है। अब इस सेक्शन में ट्रेन संचालन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुचारू रूप से होने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, ब्रिज संख्या 130 का यह सुदृढ़ीकरण कार्य भारतीय रेलवे की तकनीकी क्षमता, सतर्कता और यात्री सुरक्षा के प्रति उसकी गंभीरता का एक मजबूत उदाहरण बनकर सामने आया है।